

“ मुख्य समाचार ”

- राज्य सरकार ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्टअप योजना को दी मंजूरी—नई इकाईयां स्थापित करने के लिए ऋण पर वित्तीय राहत देगी सरकार।
- नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश में आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य व केन्द्र के सांझे प्रयासों पर दिया बल।
- उप—मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा—आपदा प्रभावित क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की बहाली का कार्य युद्धस्तर पर जारी।
- सेवा पखवाड़े के तहत भाजपा द्वारा प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित—2 अक्टूबर तक होंगे कई कार्यक्रम।
- केन्द्र सरकार के प्रयासों से कृषि क्षेत्र और किसानों के जीवन में आया बदलाव।

सुख्खू

राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से आतिथ्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्टअप योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत नई पर्यटन इकाईयां स्थापित करने और मौजूदा होमस्टे इकाईयों का विस्तार व स्तरोन्नत करने के लिए ऋण पर वित्तीय राहत दी जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुख्खू ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में योजना के तहत ऋण पर 3 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 4 प्रतिशत व जनजातीय क्षेत्रों में 5 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी। उन्होंने बताया कि ये सुविधा अधिकतम तीन वर्षों की अवधि के लिए और 2 करोड़ रुपये के ऋण पर उपलब्ध होगी और ये योजना केवल बोनाफाईड हिमाचलियों के लिए है।

जयराम

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश में इस मॉनसून सीजन में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान पर चिंता जताई है। आकाशवाणी से आज विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 से लेकर आपदा ने प्रदेश को आर्थिक रूप से काफी पीछे धकेल दिया है और राज्य व केन्द्र सरकारों को मिलकर इसके लिए सहयोग करना चाहिए।

जयराम ठाकुर ने प्रदेश में आपदा के नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दी गई आर्थिक मदद के लिए उनका आभार व्यक्त किया है।

मुकेश अग्निहोत्री

उप—मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की बहाली को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि आपदाग्रस्त धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में जलशक्ति विभाग की प्रभावित कुल 70 योजनाओं की बहाली का कार्य युद्धस्तर पर जारी है। अग्निहोत्री ने कहा कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद विभाग के कर्मचारियों के अथक प्रयासों से अब तक 48 योजनाएं आंशिक रूप से बहाल कर दी गई हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि धर्मपुर क्षेत्र की जनता की सुविधा के लिए सरकार हर स्तर पर सक्रिय है और जल्द ही सभी पेयजल योजनाओं को कार्यशील कर दिया जाएगा।

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मेलों और त्यौहारों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया है। बिलासपुर जिले के जुखाला में आयोजित तीन दिवसीय जिला स्तरीय सायर मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए आज उन्होंने ये विचार व्यक्त किए। राज्यपाल ने कहा कि मेले नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है और समाज में आपसी भाईचारे व सदभाव को भी बढ़ावा देते हैं। शिव प्रताप शुक्ल ने उपायुक्त बिलासपुर को सायर मेला समिति के माध्यम से महिला मण्डलों को एक लाख रुपए की राशि प्रदान करने के निर्देश दिए।

कुलदीप पठानिया

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने अगले साल आयोजित होने वाली श्री मणिमहेश यात्रा से पहले श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुविधा को लेकर एसओपी तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस मॉनसून सीजन के दौरान चम्बा जिला में प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की समीक्षा को लेकर चम्बा में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को नदी-नालों व संवेदनशील क्षेत्रों में अवैध डम्पिंग पर अंकुश लगाने के निर्देश भी दिए।

भाजपा सेवा पखवाड़ा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को देश भर में सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। जिसके तहत 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक विभिन्न विषयों पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आज भाजपा द्वारा शिमला के कालीबाड़ी परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया जिसका शुभारंभ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सेवा पखवाड़ा के तहत आज प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किए गए और दो अक्टूबर तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष में पूरे देश भर में और हिमाचल प्रदेश में सेवा पखवाड़ा बनाया जा रहा है। 68 स्थान के ऊपर स्वास्थ्य जांच शिविर लगाएंगे। आज पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान के कार्यक्रम मोदी जी ने संदेश दिया यह मेरा देश है मेरा शहर है मेरा गांव है इसको साफ रखना मेरी जिम्मेदारी है। उनके उसे संदेश के अनुसरण पर पूरा देश आगे बढ़ा देश को स्वच्छ रखने के लिए उन्होंने 12 करोड़ गरीबों के घरों में शौचालय बनाने का काम किया।

सेवा पर्व

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सेवा और सुशासन मंत्र से अभिप्रेरित सरकार प्रगति और परिवर्तन के लिए लगातार काम कर रही है। विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में आज, कृषि क्षेत्र में परिवर्तन और किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में नरेन्द्र मोदी सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया जा रहा है।

कृषि भारत की अर्थव्यवस्था और संस्कृति की रीढ़ है। कृषि से लाखों परिवारों का भरण-पोषण होता है और यह राष्ट्र की पहचान को परिभाषित करती है। अमृत काल में प्रवेश के साथ, भारत के सशक्त किसान, देश को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता से नेतृत्व की ओर ले जाने के लिए तैयार हैं। पिछले 11 वर्षों में, कृषि मंत्रालय का बजट लगभग 22 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 1 लाख 37 हजार करोड़ रुपये से अधिक किया गया है। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में दोहराया है भारत के किसान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं और किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। किसानों के हितों को सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर काम करते हुए, सरकार ने पिछले 11 वर्षों के दौरान खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में 81 प्रतिशत से 226 प्रतिशत तक की उल्लेखनीय वृद्धि की है। किसानों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए,

सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि शुरू की है। इस योजना के तहत पिछले छह वर्षों के दौरान तीन लाख नब्बे हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की गई है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना में 3000 रुपये की मासिक पेंशन का प्रावधान है। इस योजना के तहत लगभग 25 लाख किसानों को नामांकित किया गया है। ऋण तक आसान और किफायती पहुँच प्रदान करने के लिए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर पाँच लाख रुपये कर दिया गया है। इस योजना के तहत अब तक 10 लाख करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया जा चुका है। किसानों और खाद्य सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि अवसंरचना निधि, प्रधान मंत्री किसान समृद्धि केंद्र, राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) सहित अन्य प्रमुख योजनाएं भी हैं। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।

शांडिल

स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश के लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आज शिमला स्थित राज्य डेंटल कॉलेज की रोगी कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए 2 सौ चिकित्सकों और 4 सौ नर्सों के पद भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 9 जिलों में आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों 28 डायलिसिस केन्द्र स्थापित करने को मंजूरी दी गई है ताकि लोगों को घर के पास बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। शांडिल ने दंत सेवाओं को सुव्यवस्थित करने पर भी विशेष बल दिया।

धर्माणी

नगर नियोजन व तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है प्रदेश सरकार का प्रमुख ध्येय आम लोगों का कल्याण व जनसमस्याओं का समाधान है। घुमारवीं विधानसभा की करलोटी पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब तक कृषि और बागवानी से संबंधित उच्च स्तर के ही पाठ्यक्रम उपलब्ध थे, लेकिन अब प्रदेश सरकार ने आईटीआई स्तर पर भी कृषि, बागवानी और पशुपालन से जुड़े पाठ्यक्रम शुरू किए हैं।

मौसम

राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में रूक-रूककर मॉनसून की वर्षा का क्रम जारी है। मौसम विज्ञान केन्द्र शिमला ने कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, सोलन, शिमला और सिरमौर जिलों में आज कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल से प्रदेश के मौजूदा मौसम में सुधार की सम्भावना जताई है।

“ मुख्य समाचार एक बार फिर ”

- राज्य सरकार ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्टअप योजना को दी मंजूरी—नई इकाईयां स्थापित करने के लिए ऋण पर वित्तीय राहत देगी सरकार।
- नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश में आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य व केन्द्र के सांझे प्रयासों पर दिया बल।
- उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा—आपदा प्रभावित क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की बहाली का कार्य युद्धस्तर पर जारी।
- सेवा पखवाड़े के तहत भाजपा द्वारा प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित—2 अक्टूबर तक होंगे कई कार्यक्रम।
- केन्द्र सरकार के प्रयासों से कृषि क्षेत्र और किसानों के जीवन में आया बदलाव।